भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1552
जिसका उत्तर सोमवार, 21 जुलाई, 2014 को दिया जाना है

ऑटोमोबाइल उद्योग का संवर्धन

1552. श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में वाहन क्षेत्र को कोई प्रोत्साहन पैकेज देने का प्रस्ताव है;
(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा देश में ऑटोमोबाइल क्षेत्र के विकास के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री पोन्. राधाकृष्णन)

(क और ख): जी, नहीं।

(ग): सरकार ने भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग की उच्च वृद्धि दर को बनाए रखने और भारतीय बाजार में आकर्षण कायम रखने तथा भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता को और बढ़ाने के लिए एक दस वर्षीय ऑटोमोटिव मिशन प्लान (एएमपी) 2006-16 तैयार किया है। यह मिशन प्लान इस सेक्टर के लिए सरकारी नीति का महत्वपूर्ण आधार है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने इस सेक्टर को सुदृढ़ करने के लिए कुछ अन्य नई पहल भी की हैं, जैसे ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद् (एएसडीसी) का गठन, ऑटोमोटिव उपकर निधि से अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण, होमोलोगेशन और टेस्टिंग के लिए विश्वस्तरीय अवसंरचना की स्थापना के लिए नैशनल ऑटोमोटिव रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (नैट्रिप) का प्रारंभ, ऑटो अनुसंधान और विकास कुशलता के केन्द्र और सहयोगी अनुसंधान और विकास की आवश्यकता को पूरा करने तथा नेट्रिप के कार्यकलापों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक शीर्ष समन्वय निकाय के रूप में नैशनल ऑटोमोटिव बोर्ड (एनएबी) की स्थापना। सरकार ने देश की जैविक ईंधन पर निर्भरता को कम करते हुए आम लोगों को स्वच्छ परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नैशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान (एनईएमएमपी) 2020 के तहत देश में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पहल भी की है। एनईएमएमपी 2020 में वर्ष 2020 के अंत तक 6-7 मिलियन हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रयोग में लाने की परिकल्पना की गई है। हाल में, सरकार ने वाहनों पर उत्पाद शुल्क दरों को भी कम कर दिया है जिससे पिछले कुछ माह में बिक्री को बढ़ाने में सहायता मिली है।

*****